तिब्बत देश

बंजारा ज़िंदगी पर चीन का उपनिवेशवादी हमला

इन दिनों चीन में चेंग्दू–सिलिंग हाइवे पर यात्रा करते समय एक अजीब दृश्य आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। सड़क के दोनों ओर चलने वाले मीलों लंबे हरे मैदानों के बीचों बीच थोड़ी–थोड़ी दूरी पर ईंटों के रंग वाली और सलीकेदार दिखने वाली सौ–पचास घरों की बस्ती का कोई पैबंद अचानक हरियाली के क्रम को तोड़ कर जंगल में 'सभ्यता' का अटपटा सा अहसास कराता है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर इन नई नकोर बस्तियों से जिंदगी एकदम गायब है क्योंकि या तो वहां निर्माण कार्य अभी चल रहा है या फिर घरों में रहने वालों का अभी आना बाकी है। ये घर तिब्बती बंजारों को बसाने के लिए बनाए जा रहे हैं जो तिब्बत पर चीनी कब्जे के साठ साल बाद भी घुमक्कड़ी का वही सिलसिला जारी रखे हुए हैं जो अनंत काल से पूरे तिब्बत में चला आ रहा है।

यह काम चीन सरकार के उस खास अभियान के तहत शुरू किया गया है जिसके बारे में बीजिंग के कम्युनिस्ट शासकों का कहना है कि यह सब तिब्बती बंजारों के 'आर्थिक–सामाजिक विकास' और तिब्बत के 'पर्यावरण की रक्षा' के लिए किया जा रहा है। इस अभियान के तहत तकरीबन साढ़े 22 लाख बंजारों को बसाने की योजना है जो कुल तिब्बती आबादी का एक तिहाई है। मूल तिब्बत के जिन खम और आम्दो प्रांतों में चेंग्दू और सिलिंग के बीच का यह इलाका पड़ता है उन्हें चीन सरकार तिब्बत का नहीं बल्कि चीन का हिस्सा बताती है। ये वही दो प्रांत हैं जिन्हें तिब्बत पर चीनी कब्जे से एक साल पहले 1949 वाले पहले हमले में चीनी सेना ने कब्जा लिया था। बाद में 1960 वाले दशक में तिब्बत के 'पुनर्गठन' नाम पर इन दोनों प्रांतों के अधिकांश हिस्सों को तिब्बत से काटकर आसपास के चीनी प्रांतों में मिला दिया गया था। बाकी बचे एक तिहाई तिब्बत को 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' (आटोनॉमस रिजन ऑफ टिबेट –– टार) का नाम देकर चीन इसे असली 'तिब्बत' के रूप में दुनिया के सामने पेश करता है।

लेकिन 2008 मार्च में जब यही दोनों प्रांत तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का असली केंद्र बन कर उभरे तो चीन सरकार के लिए दुनिया को यह समझाना मुश्किल हो गया कि 'चीनी' इलाकों में इतने तिब्बती कहां से आए और वे चीन सरकार से क्यों मुक्ति चाहते हैं? इन प्रदर्शनों में तिब्बती बंजारों ने भी भारी भूमिका निभाई थी। इससे पहले 1950–60 वाले दौर में भी गोलोक, खम और आम्दो के चीन विरोधी छापामार सशस्त्र संघर्ष में बंजारों में बड़ी भूमिका निभाई थी। स्वभाविक है कि उन्हें स्थायी बस्तियों में बसने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि चीनी उपनिवेशवाद के खिलाफ तिब्बती चुनौती को कमजोर किया जा सके।

सिचुआन, चिंघाई और गांसू की अपनी हाल की यात्रा के दौरान मुझे ऐसी कुछ बंजारा बस्तियों को देखने का मौका मिला जहां जिंदगी दिखाई तो देती है लेकिन निहायत विद्रूप रूप में। कहां खुले आकाश के नीचे पहाड़ी ढलानों पर याक के बालों से बने विशाल तंबुओं की स्वच्छंद जिंदगी और कहां छोटे छोटे फ्लैटों का दमघोंटू वातावरण। सरकारी आदेश पर अपने अधिकांश जानवरों को बेचने के बाद नए काम धंधे शुरू करने में असमर्थ ज्यादातर बंजारों का पैसा नए घर की कीमत अदा करने और खाली बैठने में उड़ चुका है। उदाहरण के लिए चिंघाई के गोलोक में तावो इलाके में 2009 के दौरान अमीर तिब्बती बंजारा परिवारों की सालाना आमदनी भी केवल एक चौथाई रह गई है। इसने कई तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा कर दी हैं। कई जगह से बंजारों और सरकारी अधिकारियों के बीच टकराव, प्रदर्शनों और गिरफ्तारियों की खबरें आना आम बात है।

चेंग्दू–सिलिंग हाइवे का दृश्य दिखाता है कि चीन सरकार किस हद तक बंजारों की जिंदगी पर अंकुश लगाने पर अड़ी हुई है। वहां घास की ढलानों पर चरते हुए सैंकड़ों याक और भेड़ों के समूह भी दिखते हैं और बंजारों के नीले प्लास्टिक वाले चीनी तंबुओं के सामने मोटर साइकिल और एक–दो एसयूवी गाड़ियां दिखना आम बात है। लेकिन इसके साथ साथ घास के मैदानों को बीचों–बीच बांटती हुई और सड़क के दोनों ओर मीलों तक चलने वाली कांटेदार तारों की लंबी बाड़ देखकर समझ आता है कि बंजारों और उनके जानवरों के इधर–उधर घूमने पर पाबंदी लगाए जाने का अर्थ क्या है। अगले चरण में इन बंजारों को अपने जानवर औने–पौने दामों में चीनी बूचड़खानों के हाथ बेचकर माचिस की डिब्बियों जैसे घरों में स्थायी तौर पर रहने को मजबूर कर दिया जाएगा।

तिब्बती बंजारों को जबरन एक स्थान पर बसाए जाने का यह क्रम वैसे तो 1990 वाले दशक से चल रहा है। लेकिन शुरू में केवल उन्हीं इलाकों से उन्हें हटाया जाता था जो या तो चीनी सैनिक छावनियों, नए राजमार्गों और नए खान क्षेत्रों में घुमक्कड़ी करते थे। चीन से तिब्बत तक रेलगाड़ी लाने के दौरान भी ल्हासा–गोरमो के बीच पड़ने वाले विशाल ढलानों और मैदानों से हटाकर उन्हें स्थायी बस्तियों में ठूंसने का अभियान चलाया गया था। लेकिन अब 'टार' के बाहर खम और आम्दो प्रांतो के तथाकथित 'चीनी' इलाकों से तिब्बती बंजारों को बीन बीनकर उन्हें छोटी–छोटी बस्तियों में बांधने का नया अभियान चलाया जा रहा है।

हालांकि चीन सरकार याक और भेड़ों से घास के मैदानों की रक्षा करने का नाम देकर इस अभियान पर पर्यावरण की रक्षा के पुण्यकार्य का मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन 1949 के बाद विशाल पैमाने पर इस इलाके में तिब्बती जंगलों को काटकर और खनिजों को लूटकर चीन ने तिब्बत के पर्यावरण को जिस भयावह तरीके से लगभग स्थायी तौर पर नष्ट किया है उसकी वह चर्चा नहीं करना चाहती। खुद चीनी नेता और वैज्ञानिक मानते हैं कि 1950 और 1985 के बीच तिब्बती जंगलों का क्षेत्रफल 2 करोड़ 52 लाख हैक्टेयर से घटकर केवल 1 करोड़ 36 लाख हैक्टेयर रह गया। इसकी कीमत चीन की यैलो रिवर, मेकांग और यांग्त्सी नदियों की बरबादी के रूप में अब सामने आ रही है। लिथांग से सिलिंग की तरफ अपनी एक यात्रा के दौरान मीलों तक पेड़ों की कटाई से नंगे हुए पहाड़ और ढलानों पर फैले कटे पेड़ों के तनों का सिलसिला इतना लंबा था कि उकताकर मुझे अपनी फोटोग्राफी बीच में ही बंद करनी पड़ी।

जिन घास के मैदानों की बात आज चीन सरकार कर रही है, चेंग्दू–सिलिंग हाइवे और चेंग्दू–ल्हासा जैसे राजमार्गों के आसपास इन मैदानों की बरबादी का सिलसिला असल में चीन से लाखों की संख्या में आए सैनिकों और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने 1949 में शुरू किया था। खाने और सजावट के लिए चीलों और दूसरे पक्षियों के दशकों तक चले शिकार के उनके शौक ने सैंकड़ों मील के इलाके में चूहों की भरमार कर दी थी जिसके कारण घास के मैदान खोखले हो गए और चरागाहों को भारी नुकसान पहुंचाया था। पशु वैज्ञानिकों का कहना है कि याक द्वारा चाटकर घास खाने की आदत और भारी मात्रा में गोबर देने तथा तिब्बती बंजारों की संस्कृति में चरागाहों में विशेष चक्र बनाए रखने की परंपरा के कारण ही तिब्बती चरागाह उन दूरस्थ इलाकों में बचे रहे जहां चीनी नहीं पहुंच पाए।

ऐसे में तिब्बतियों के इस आरोप में दम दिखता है कि इस चीनी अभियान का असली लक्ष्य बंजारों को जंगलों से हटाकर, छोटी बस्तियों में बसाकर और उन पर पुलिस निगरानी बढ़ाकर तिब्बती आजादी के आंदोलन को कुचलना है। और इससे भी बड़ा कारण यह है कि बंजारों से खाली कराए जा रहे इन इलाकों में चीन सरकार लाखों की संख्या में चीनी नागरिकों को बसाने के उस अभियान को आगे बढ़ाने जा रही है जिसका उपनिवेशवादी इस्तेमाल वह बाकी तिब्बत, चीनी कब्जे वाले भीतरी मंगोलिया और पूर्वी तुर्किस्तान (सिंकियांग) में पहले ही कर चुकी है। 2007 में तिब्बती कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव ने कहा था कि बंजारों के पुनर्वास का अभियान सरकार की आर्थिक और राजनीतिक नीति का हिस्सा है। सवाल यह है कि खुद को मानवाधिकारों और आजादी का पक्षधर कहनी वाली दुनिया की बिरादरी इस चीनी पाप पर क्या कदम उठाती है?

— विजय क्रान्ति

धन्यवाद हिमाचल समारोह में स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों को तिब्बतियों ने सम्मानित किया

परम पावन दलाई लामा द्वारा गेंधुन छोक्यी निमा को पिछले पंचेन लामा का अवतार घोशित किए जाने के तीन दिन बाद ही 17 मई 1995 को चीनी अधिकारियों ने गोपनीय तरीके से निमा और उनके परिवार का अपहरण कर लिया। तब वह सिर्फ छह साल के थे। गेंधुन छोक्यी निमा पिछले माह 21 साल के हो गए हैं, लेकिन वह कहां हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं है और वह सही सलामत हैं या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।

(टिबेट डॉट नेट, 1 मई, धर्मशाला)

निर्वासित तिब्बती समुदाय का पिछले 50 साल से समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक धन्यवाद हिमाचल समारोह के दूसरे दिन स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। परम पावन दलाई लामा के मसूरी से धर्मशाला आने के ऐतिहासिक 50 साल पूरा होने के अवसर और हिमाचल सरकार एवं वहां की जनता को धन्यवाद देने के लिए आयोजित समारोह की अध्यक्षता परम पावन दलाई लामा और केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह ने की। इस अवसर पर सुगलागखांग के मुख्य बौद्ध मंदिर में शनिवार की सुबह सैंकड़ों तिब्बतियों के साथ सैकड़ों भारतीय नागरिक भी शामिल हुए जिनमें कई वरिष्ठ नागरिक भी थे। निर्वासित तिब्बतियों की राजधानी के लिए धर्मशाला का चुनाव करने पर आभार प्रकट करते हुए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि परम पावन को एक सम्मानित अतिथि बनाकर स्थानीय नागरिकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

दुनिया भर के तिब्बती समुदाय ने किगुदो भूकंप पीड़ितों के लिए प्रार्थना किया

(टिबेट डॉट नेट, 6 मई, धर्मशाला)

दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले तिब्बती समुदाय के लोगों ने सोमवार, 4 मई को एक विशेष प्रार्थना का आयोजन किया। यह प्रार्थना सभा 14 अप्रैल को तिब्बत के किगुडो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप में मारे गए लोगों के तीन हफ्ता बीतने पर एक रिवाज का हिस्सा था। स्थानीय समयानुसार सुबह 7.49 बजे कशग के निर्देश पर दुनिया भर में तिब्बती समुदाय के लोग जुटे और पहले एक मिनट के लिए मौन रखा गया। ताइपेई स्थित परम पावन दलाई लामा के द टिबेट रिलीजियस फाउंडेशन ने भी 4 मई को ताइपेई और ताओयोन शहर में एक जन प्रार्थना सभा का आयोजन किया। पूज्य जांगत्से छोजे रिनपोछे ने फाउंडेशन की प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया और उनके साथ ताईपेई के विभिन्न बौद्ध केंद्रों से आए हुए 50 तिब्बती भिक्षु भी थे। परम पावन के फाउंडेशन के कर्मचारी और ताईपेई शहर में रहने वाले तिब्बती भी इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए। ताओयुन के छेनरी–सिग तिब्बती बौद्ध केंद्र में भी एक प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। तायोयुन शहर में रहने वाले चार तिब्बती भिक्षु और वहां के स्थानीय तिब्बती नागरिक इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए।

पंचेन लामा को तुरंत रिहा करने की मांग की टीवाईसी ने

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 17 मई)

निर्वासित तिब्बती समुदाय के आज़ादी समर्थक सबसे बड़े संगठन तिब्बती युवा कांग्रेस के सदस्यों ने सोमवार एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का आयोजन किया और चीनी नेतृत्व से मांग की कि वह 11वें पंचेन लामा गेनधुन छोक्यी निमा को तत्काल रिहा करे। गेनधुन को दलाई लामा ने 1995 में दलाई लामा ने 11वें पंचेन लामा के रूप में पहचान की थी। गौरतलब है इस सोमवार को पंचेन लामा के बंदी बने 15 साल हो गए हैं। परम पावन दलाई लामा द्वारा गेंधुन छोक्यी निमा को पिछले पंचेन लामा का अवतार घोशित किए जाने के तीन दिन बाद ही 17 मई 1995 को चीनी अधिकारियों ने गोपनीय तरीके से निमा और उनके परिवार का अपहरण कर लिया। तब वह सिर्फ छह साल के थे। गेंधुन छोक्यी निमा पिछले माह 21 साल के हो गए हैं, लेकिन वह कहां हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं है और वह सही सलामत हैं या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पिछले कई सालों से दुनिया भर के तिब्बती नागरिक और उनके समर्थक नियमित रूप से उनके जन्म दिन और गायब होने की घटना को "पंचेन लामा को रिहा करो" अभियान के रूप में मनाते हैं।

परम पावन के दूतों ने चीन से कहा कि वह दलाई लामा के अनुरोध को माने

(फायूल, धर्मशाला, 13 मई)

तिब्बती नेता दलाई लामा के विशेष दूत ने चीन

से अनुरोध किया है कि वह परंपरागत तिब्बती प्रांत खम के केगुदो इलाके का दौरा करने के परम पावन के अनुरोध पर सकारात्मक ढंग से विचार करे। खम को अब क्विंघई प्रांत के युशु तिब्बती स्वायत्तशाासी प्रशासन में शामिल किया गया है। परम पावन दलाई लामा के विशेष दूत लोदी ग्यालत्सेन ग्यारी ने बुधवार को वायस ऑफ अमेरिका के तिब्बती कार्यक्रम कुनलेंग में बातचीत के दौरान यह बात कही। ग्यारी ने भूकंप के मामले को इस्तेमाल करने की निर्वासित तिब्बती सरकार पर चीन द्वारा लगाए गए आरोपों की कड़ी आलोचना की। ग्यारी ने कहा, चीनी नेता यदि परम पावन दलाई लामा को केगुंडु के दौरे पर जाने की इजाजत देने की दूरदर्शिता दिखाने में सक्षम हुए तो इससे उनकी हर जगह के तिब्बतियों, खासकर भूकंप से प्रभावित तिब्बतियो के बीच अच्छी छवि बनेगी।

ग्यारी ने कहा परम पावन के इस अनुरोध को लेकर उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य के संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया था। गत 17 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन में परम पावन ने केगुडु जाने की इच्छा जाहिर की थी ताकि वे दैवी आपदा से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करें और उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से राहत दें, लेकिन चीन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।

निर्वासित तिब्बतियों ने एक तिब्बती नागरिक को मौत की सजा देने का विरोध किया

(फायूल, धर्मशाला, 29 मई)

निर्वासित तिब्बती सरकार ने इस हफ्ते चीन सरकार द्वारा एक तिब्बती नागरिक को मौत की सजा और पांच अन्य को लंबे समय तक जेल की सजा देने की कड़ी आलोचना की है। तिब्बत सरकार के सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की मंत्री केसांग वाई टाकला ने बताया, "केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करती है कि चीन सरकार ने एक बार फिर एक तिब्बती नागरिक को मौत की सजा और पांच अन्य तिब्बती नागरिकों को लंबे समय तक जेल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि ल्हासा माध्यमिक जन अदालत ने 23 साल के सोनम सेरिंग को दो साल के लिए विलंबित मौत की सजा मंगलवार को सुनाई है। सोनम ऐसे सातवें तिब्बती नागरिक हैं जिन्हें मार्च, 2008 में चीन विरोधी प्रदर्शनों भाग लेने के आरोप में मौत की सजा दी गई है। पिछले साल अक्टबूर में इसी आरोप में दो तिब्बती नागरिकों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार इसी अदालत ने पांच अन्य तिब्बती नागरिकों को पांच से लेकर सात साल तक के जेल की सजा सुनाई है। इन पर आरोप हैं कि इन्होंने दंगों के बाद सोनम सेरिंग को अपने घर में शरण दी और उनके विदेश भागने की तैयारी में मदद की। टाकला ने कहा, "जिस तरह से बिना खुले और निष्पक्ष मुकदमे के मनमाने तरीके से इतनी सख्त सजा दी गई है, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं।" टाकला ने कहा कि अदालत का हालिया आदेश चीन के पहले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना (2009–10) के पूरी तरह खिलाफ है। इस कार्य योजना में कहा गया है कि किसी को मौत की सजा देने के मामले में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए और इसमें न्यायिक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन होना चाहिए। अपने बयान में टाकला ने निर्वासित सरकार के इस पुराने अनुरोध को फिर से दोहराया कि, "चीन को अपनी इच्छा से ही सभी बंदियों को रिहा कर देना चाहिए और तिब्बत की दशा के अध्ययन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को जाने की इजाजत देनी चाहिए।" टाकला ने चीन सरकार और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसी संस्थाओं से यह अनुरोध भी किया कि वे "तिब्बत में मानवाधिकारों की निरंतर बिगड़ती स्थिति पर ध्यान दें।" निर्वासित तिब्बती सरकार ने इसके पहले छह तिब्बती नागरिकों को मौत की सजा देने की आलोचना करते हुए एक अलग से बयान जारी किया है।

"चीन को अपनी इच्छा से ही सभी बंदियों को रिहा कर देना चाहिए और तिब्बत की दशा के अध्ययन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को जाने की इजाजत देनी चाहिए।" टाकला ने चीन सरकार और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसी संस्थाओं से यह अनुरोध भी किया कि वे "तिब्बत में मानवाधिकारों की निरंतर बिगड़ती स्थिति पर ध्यान दें।"

श्रीलंका ने अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को दलाई लामा से मिलने से रोकाः रिपोर्ट

(फायूल, 5 मई, धर्मशाला)

एक प्रमुख बौद्ध देश श्रीलंका ने अपने राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान कुमार संगकारा और अन्य

पूर्वी लद्दाख के इन क्षेत्रों में चीनी आक्रामता में इस साल 27 फीसदी से 52 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ ट्रिग हाइट्स क्षेत्र में इस साल चीनी आक्रामकता की 30 घटनाएं देखी जा चुकी हैं।

खिलाड़ियो को इस आशंका की वजह से परम पावन दलाई लामा से मिलने से रोक दिया है कि इससे चीन नाराज हो जाएगा। मंगलवार को मीडिया में यह खबरें प्रकाशित हुई हैं। संगकारा और पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने से कहा गया कि वे आईपीएल की किंग्स एलेवन पंजाब टीम के साथ न जाएं जो पिछले महीने धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती नेता से शिष्टाचार मुलाकात के लिए गए थे। श्रीलंका क्रिकेट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कोलंबो में मीडिया को यह जानकारी दी है। श्रीलंका क्रिकेट सचिव निशांत रणतुंगा ने एएफपी को बताया कि कुमार और महेला को यह निर्देश दिया गया था कि वे तिब्बती नेता से न मिलें। यह विदेश मंत्रालय का निर्देश था जो हमें खेल मंत्रालय के माध्यम से मिला था।

भारत ने चीन सीमा पर सड़क निर्माण कार्य तेज किया

चीन ने तिब्बत में करीब 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, 1118 किलोमीटर रेलमार्ग और कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है जिससे वह एक माह से भी कम समय में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को भारतीय सीमा पर तैनात कर सकता है।

(डीएच न्यूज सर्विस, 11 मई, नई दिल्ली)

भारत आखिरकार अपनी नींद से जाग गया है और चीन के साथ अपनी विवादास्पद सीमा पर इसने 5,000 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क को पूरा करने के लिए काम तेज कर दिया है। चीन के रेलमार्ग, सड़क और वायु संपर्क के आधुनिकीकरण योजना से मुकाबले के लिए सरकार की कार्ययोजना का विवरण देते हुए रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने मंगलवार को अपने मंत्रालय से जुड़े सांसदों की एक परामर्श समिति को बताया कि सीमा सड़क संगठन –बीआरओ– सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें बनाने के लिए जोरशोर से लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के समानांतर महत्वपूर्ण सड़कें बनाने के लिए एक नया संगठन बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि चीन ने भारतीय सीमा पर सड़कों, रेल और वायु संपर्क में तेजी से सुधार किया है जिससे आपात काल में तत्काल सैनिकों को सीमा तक भेजने के मामले में वह भारत से आगे हो गया है। चीन ने तिब्बत में करीब 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, 1118 किलोमीटर रेलमार्ग और कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है जिससे वह एक माह से भी कम समय में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को भारतीय सीमा पर तैनात कर सकता है।

चीन लगातार कर रहा है सीमा का उल्लंघन

(टीएनएन, मंगलवार, 11 मई, नई दिल्ली)

चीन बिना किसी भय के रियल एवं वर्चुअल दुनिया में लगातार भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रहा है। साइबर हमलों के साथ ही चीन लगातार 4,057 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लगातार बेध रहा है।

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पिछले हफ्ते में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ट्रिग चोटी और पानगांग सो झील क्षेत्र में चीन की जनमुक्ति सेना के मोटर से चलने वाले सशस्त्र गश्ती दल द्वारा सीमा के अतिक्रमण की कम से कम तीन घटनाएं देखी गई हैं।

पूर्वी लद्दाख के इन क्षेत्रों में चीनी आक्रामता में इस साल 27 फीसदी से 52 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। एक सूत्र ने बताया कि सिर्फ ट्रिग हाइट्स क्षेत्र में इस साल चीनी आक्रामकता की 30 घटनाएं देखी जा चुकी हैं। इसी प्रकार पानगांग सो झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर चीनी पैदल, वाहन और नाव गश्ती दल द्वारा नियमित रूप से रिकॉर्ड अतिक्रमण की घटनाएं देखी गई हैं।

चीन ने आरोप लगाया, दलाई लामा भारत को खुश करने के लिए क्रिकेट से झूठा प्यार दिखा रहे हैं

(फायूल, धर्मशाला, 12 मई)

चीन ने तिब्बती नेता दलाई लामा पर व्यंग्य कसते हुए कहा है कि भारत को खुश करने के लिए क्रिकेट से झूठा प्रेम दिखा रहे हैं। दलाई लामा धर्मशाला में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग के क्रिकेट मैच देखने गए थे, जिसके बाद चीन ने यह आरोप लगाया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली में प्रकाशित एक लेख में आरोप लगाया गया है कि दलाई लामा भारत सरकार को खुश करने के लिए खुद को भारत का

बेटा बताते हैं और भारत के सबसे लोकप्रिय खेल से प्यार दिखाने का नाटक कर रहे हैं।

लेख में कहा गया है कि धार्मिक नेता भारत की सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट में हिस्सा लेकर अपने को भारत का सच्चा सपूत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है और दलाई लामा निश्चित रूप से अपने पिता के साथ इसका आनंद उठाना चाहते हैं क्योंकि वे भारत का सपूत बनना चाहते हैं।

जयराम विवाद में चीनी मीडिया भी कूद पड़ी

(दि हिंदू, 12 मई, बीजिंग)

अब पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश की बीजिंग में दी गई टिप्पणी पर उठे बवाल में चीनी मीडिया भी कूद पड़ी है। चीनी मीडिया ने चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ बोलने के लिए जयराम की तारीफ की है, लेकिन ब्रह्मपुत्र बांध पर बनने वाले चीनी बांध पर जयराम की टिप्पणी के लिए चीनी मीडिया ने उनकी आलोचना की है।

चीन के सरकारी अंग्रेजी अखबार चाइना डेली ने मंगलवार को एक संपादकीय लिखकर श्री रमेश का यह कहते हुए समर्थन किया कि भारत में सुरक्षा कारणों से चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवी से उपकरणों के आयात पर लगे प्रतिबंध की खबरों से चीन–भारत की दोस्ती ढंडी पड़ सकती है।

अखबार ने भारत पर कभी–कभार ही लिखे जाने वाले शीर्ष संपादकीय लेख में कहा है कि इस संबंध में भारतीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश की टिप्पणी समझदारी भरी है।

सरकारी नियंत्रण वाले इस अखबार का काफी हद तक उद्देश्य विदेशी पाठकों तक पहुंचना है। अखबार ने दोनों देशों से आह्वान किया है कि वे अपने मौजूदा व्यापारिक गतिरोधों को निष्ठा से दूर करें।

अखबार ने लिखा है कि पिछले हफ्ते रमेश ने बीजिंग में कहा था कि भारत को चीनी निवेश के बारे में ज्यादा नरम रवैया अपनाना चाहिए और निरर्थक प्रतिबंधों को दूर करना चाहिए।

तिब्बती लेखक वुएजेर को करेज इन जर्नलिज्म अवॉर्ड

(फायूल, धर्मशाला, 14 मई)

इंटरनेषनल वुमेंस मीडिया फाउंडेषन ने तिब्बती लेखक वुएजर को साल 2010 का करेज इन जर्नलिज्म अवॉर्ड देने का फैसला किया है। यह अवॉर्ड दुनिया भर की उन महिला पत्रकारों की बहादुरी को एक मान्यता की तरह है जो भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने और मानवाधिकारों की वकालत में राजनीतिक उत्पीड़न, शरीरिक चोट या मौत का शिकार हो जाती हैं। वुएजर के अलावा यह अवॉर्ड कोलंबिया की खोजी पत्रकार क्लॉडिया डुक्यू और तंजानिया की फ्रीलांस पत्रकार विकी नतेटेमा को भी दिया जाएगा। इंटरनेशनल वुमेंस मीडिया फाउंडेशन –आईडब्ल्यूएमएफ–एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर की समाचार मीडिया में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करता है ताकि प्रेस को और आजादी मिल सके। आईडब्ल्यूएमएफ नेटवर्क में दुनिया भर के 130 से अधिक देशों के पुरुष एवं महिला पत्रकारों को शमिल किया गया है।

करेज इन जर्नलिज्म अवॉर्ड की अध्यक्ष और पीबीएस न्यूज ऑर से जुड़ी वुडरफ ने कहा, वे सच को सामने लाने के लिए अपनी जीविका, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं और हम सबको खुशी देती हैं।

चीन–तिब्बत वार्ता में मदद करने को तैयार है रूस

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 17 मई)

चीन के प्रमुख सहयोगी देष रूस ने कहा है कि वह चीन और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के बीच विवाद का समाधान करने में सहयोग करने को तैयार है। रूस की सरकारी मीडिया आरआईए नोवोस्ती के अनुसार चीन एवं तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के बीच चल रहे संवाद पर रूस गहराई से नजर रखे हुए है। रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरेशन कौंसिल में अपने भाषण में लावरोव ने कहा, "दलाई लामा एवं चीन

अब पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश की बीजिंग में दी गई टिप्पणी पर उठे बवाल में चीनी मीडिया भी कूद पड़ी है। चीनी मीडिया ने चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ बोलने के लिए जयराम की तारीफ की है, लेकिन ब्रह्मपुत्र बांध पर बनने वाले चीनी बांध पर जयराम की टिप्पणी के लिए चीनी मीडिया ने उनकी आलोचना की है।

के बीच जो कुछ भी चल रहा है, हम उस पर गहराई से नजर रखे हुए हैं। हम यह जानते हैं कि चीनी नेतृत्व इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि दलाई लामा चीन के एक या किसी भी क्षेत्र में किसी तरह के राजनीतिक या अलगाववादी गतिविधियों में शामिल न हों।"

साधना चैनल पर हर दिन प्रसारित होगा बौद्ध आध्यात्मिक कार्यक्रम

"भारत हमारा गुरु है और हम इसके भरोसेमंद चेले हैं। हमने नालंदा परंपरा के अनुसार बौद्ध विद्वान तैयार किए हैं, इसलिए हमें नालंदा बौद्ध परंपरा को जिंदा रखने वाला भरोसेमंद चेला माना जा सकता है।" परम पावन ने 200 फुट के मुख्य स्तूप का नामकरण भी किया। भगवान बुद्ध को समर्पित इस स्तूप का नाम "पाटलिपुत्र करुणा स्तूप" रखा गया है।

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 25 मई)

दिल्ली के एक बौद्ध संघ ने बताया है कि साधना चैनल पर हर दिन "भद्र ज्ञान" के नाम से एक बौद्ध आध्यात्मिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा गुरुवार से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम के प्रसारण का उद्घाटन परम पावन दलाई लामा करेंगे। कार्यक्रम का संचालन करने वाली शेराब सांगपो सोसाइटी (एसएसएस) ने यह जानकारी दी है। इस सोसाइटी के प्रमुख सोना रिनपोछे हैं जो ड्रेपंग लोसेलिंग मठ के लामा अवतार और अरुणाचल विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं। रिनपोछे ने फायूल को बताया, "परम पावन दलाई लामा ने एक बार मुझे यह सुझाव दिया था कि मुझे कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे बौद्ध धर्म और हिमालय को जोड़ा जा सके। मैं समझता हूं कि यह कदम उसी दिशा में एक प्रयास है।" गुरुवार 27 मई को बुद्ध पूर्णिमा भी है जिसे तिब्बती भाषा में साका दावा कहते हैं। यह दिन भगवान बुद्ध के जीवन के तीन महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। इस दिन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का 2550वां साल पूरा हो रहा है।

परम पावन दलाई लामा ने बुद्ध पार्क का उद्घाटन किया

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला)

परम पावन दलाई लामा ने गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन किया और श्रीलंका से लाई गई महाबोधि वट वृक्ष की एक टहनी का रोपण किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार श्रीलंका, जापान, थाइलैंड, म्यामार और दक्षिण कोरिया से लाए गए बौद्ध काल के स्मृति चिह्नों को इस पार्क में स्थापित किया गया है। बिहार सरकार ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2550 साल पूरा होने के अवसर पर इस पार्क का निर्माण किया है। बिहार के राज्यपाल देवानंद कुंवर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ पहुंचे परम पावन दलाई लामा ने अत्याधुनिक बौद्ध धार्मिक पार्क के औपचारिक उद्घाटन से पहले दीप प्रज्ज्वलित किया और एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बुद्ध स्मृति पार्क के उद्घाटन समारोह में श्रीलंका, म्यांमार, जापान और थाइलैंड जैसे प्रमुख बौद्ध देशों से आए प्रतिनिधि भी शामिल हुए। परम पावन दलाई लामा ने गौतम बुद्ध की स्मृति में बने इस पार्क के उद्घाटन का आमंत्रण देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया और राज्य की अपनी यात्रा को खुशनुमा अनुभव बताया। परम पावन ने कहा, "भारत हमारा गुरु है और हम इसके भरोसेमंद चेले हैं। हमने नालंदा परंपरा के अनुसार बौद्ध विद्वान तैयार किए हैं, इसलिए हमें नालंदा बौद्ध परंपरा को जिंदा रखने वाला भरोसेमंद चेला माना जा सकता है।" परम पावन ने 200 फुट के मुख्य स्तूप का नामकरण भी किया। भगवान बुद्ध को समर्पित इस स्तूप का नाम "पाटलिपुत्र करुणा स्तूप" रखा गया है।

अमेरिका–चीन के बीच मानवाधिकारों पर दो दिन की बातचीत खत्म

(एपी, 15 मई, वाशिंगटन)

मानवाधिकारों के लिए साल 2002 के बाद अब अमेरिका एवं चीन के बीच हुई दूसरे दौर की वार्ता शुक्रवार को बिना किसी खास नतीजे के समाप्त हो गई है।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दो दिन की इस वार्ता ने दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच संबंधों में तनाव को दूर करने के लिए और नियमित वार्ताएं शुरू करने के लिए जमीनी आधार तैयार की है। अमेरिका की तरफ से वार्ता का नेतृत्व करने वाले सहायक विदेश राज्य मंत्री माइकल पोजनर ने पत्रकारों को बताया कि अगले

दौर की वार्ता अगले साल किसी समय बीजिंग में हो सकती है। दोनों देशों की योजना जल्दी ही कानूनी बातचीत शुरू करने की है। पोजनर ने कहा कि वह बीजिंग में इस महीने होने वाले उच्च स्तरीय आर्थिक एवं सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

पोजनर ने कहा, दो दिन की वार्ता में हम किसी बड़े नीतिगत या वैचारिक बदलाव की अपेक्षा नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने इसे आगे करने के लिए जमीनी आधार तैयार किया है। इस दौरान हुई चर्चा का स्वर यह था कि हम दो ताकतवर और महान देश हैं। हमारे पास ऐसे कई मसले हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। मानवाधिकार इन चर्चाओं का हिस्सा है और आगे भी यह रहेगा।

ओबामा प्रशासन चाहता है कि चीन अपने नागरिकों से बेहतर व्यवहार करे, लेकिन उसे ईरान एवं उत्तर कोरिया परमाणु हथियार, जलवायु परिवर्तन और अन्य कई जटिल मसलों पर चीन के समर्थन की भी जरूरत है।

बीजिंग में छद्म मुक्केबाजी

(टीओआई, 15 मई)

अपने बयानों से घिर चुके पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को चीन में अमेरिकी राजदूत जॉन हंट्समैन से ईष्या हो सकती है। पिछले हफ्ते जयमराम रमेश का यह बयान अखबारों में छाया रहा कि भारत में चीनी निवेश को लेकर बने भ्रम से देश को कोपनहेगन की भावना से मिले पूरे फायदों से वंचित होना पड़ सकता है, लेकिन इस दौरान अमेरिकी राजदूत की क्षमायाचक टिप्पणी पर किसी ने गौर नहीं किया। हाल में दिए एक इंटरव्यू में अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियारों की बिक्री और राष्ट्रपति की दलाई लामा से मुलाकात के संदर्भ में कहा था, –अमेरिकी प्रशासन ने चीन के कई महत्वपूर्ण हितों को ठोकर मार दिया है। चीन के कुछ विशेषज्ञों के अलावा बहुत कम लोगों ने अमेरिकी राजदूत के इस आलोचक स्वर पर और उनके द्वारा चीन के कोर इंट्रेस्ट जैसे शब्द के इस्तेमाल पर ध्यान दिया है। बीजिंग ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लगातार यह चेतावनी दी है कि चीन के साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए उसके कोर इंट्रेस्ट के प्रति अलग रवैया दिखाना होगा। नवंबर, 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के बीजिंग दौरे के अवसर पर उनके चीनी समकक्ष हू जिनताओ ने उन्हें याद दिलाया कि सामरिक पारस्परिक भरोसे की पूर्व शर्त यह है कि एक दूसरे के कोर इंट्रेस्ट और प्रमुख चिंताओं का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि चीन के कोर इंट्रेस्ट में ताइवान पर चीन की प्रभुसत्ता और तिब्बत एवं सीक्यांग में चीनी शासन को मिल रही चुनौतियां शामिल हैं। कोर इंट्रेस्ट का नया शब्द गढ़ने के अलावा चीन के इस प्रभुसत्ता के दावे में कुछ भी नया नहीं है। अपनी सीमा की रक्षा करना किसी देश के लिए सामान्य बात ही है, लेकिन यह समझ में आने वाली बात नहीं है कि आखिर चीन हर समय दोस्ती की शर्त अपने कोर इंट्रेस्ट के सम्मान को क्यों बना देता है।

दलाई लामा ने कहा, तिब्बत मसले को हल करने के लिए चीन हो गंभीर

(फायूल, धर्मशाला, 19 मई)

निर्वासित तिब्बती नेता परम पावन दलाई लामा ने कहा है कि चीनी नेतृत्व को यह स्वीकार करना चाहिए कि तिब्बत में समस्या है और उन्हें इसे हल करने के लिए गंभीरता से बातचीत शुरू करना चाहिए।

निर्वासित तिब्बती सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अमेरिका के दौरे पर गए तिब्बती नेता मंगलवार को सेडार फाल्स में चीनी भाशा के समाचार पत्र मीडिया दुओवेई से यह बात कही। रिपोर्ट के अनुसार यह इंटरव्यू दुओवेई के अध्यक्ष श्री यु पिन्हाई ने लिया। यु हांगकांग से सेडार फाल्स सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए आए थे। दलाई लामा ने कहा, "चीनी नेतृत्व को यह स्वीकार करना होगा कि कोई तिब्बत समस्या है और उन्हें इसके बारे में गंभीरता से बातचीत शुरू करनी होगी।" परम पावन से यह सवाल किया गया था कि तिब्बत मसला किस तरह का है क्या वह इस पर आगे चीनी नेतृत्व से बातचीत करना चाहेंगे। इंटरव्यू के दौरान परम पावन ने इस बात को भी

चीन के कोर इंट्रेस्ट में ताइवान पर चीन की प्रभुसत्ता और तिब्बत एवं सीक्यांग में चीनी शासन को मिल रही चुनौतियां शामिल हैं। कोर इंट्रेस्ट का नया शब्द गढ़ने के अलावा चीन के इस प्रभुसत्ता के दावे में कुछ भी नया नहीं है। अपनी सीमा की रक्षा करना किसी देश के लिए सामान्य बात ही है, लेकिन यह समझ में आने वाली बात नहीं है कि आखिर चीन हर समय दोस्ती की शर्त अपने कोर इंट्रेस्ट के सम्मान को क्यों बना देता है।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आंख

1 धर्मशाला में धन्यवाद हिमाचल समारोह में परम पावन दलाई लामा (बाएं से दूसरे) एक स्क्रॉल भेंट करते हुए। इस अवसर पर राज्य की पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीम मौजूद थे।

2 तिब्बती सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल और दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित और परमपूज्यनीय सुदर्शनजी (बाएं से छठे) के साथ एक बैठक में। फोटो–टीपीआ

3 हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इल उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल (बाएं) और बॉलीवुड अभि

4 भूकंप से बुरी तरह प्रभावित किगुदो क्षेत्र में राहत सामग्री की खेप भेजने में मदद

5 किगुदो भूकंप में मारे गए लोगों के लिए तीसरे सप्ताह में आयोजित सामूहिक प्रार्थ कालोन ट्रिपा सामदोंग रिनपोछे। फोटो–टिबेट डॉट नेट

6 तिब्बत की मदांग टाउनशिप में स्थित सीमेंट फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में तैनात

7 रूस के विदेश मंत्री सरजेई लावरोव। फाइल फोटो

8 सेरिंग वूजर

9 परम पावन के विशेष दूत कसूर लोदी ग्यारी। फोटो–टिबेट नेट

10 पटना में गुरुवार, 27 मई को बुद्ध पार्क के उद्घाटन के बाद एक पौधा रोपण की कुमार (बीच में) भी हैं। इस दिन को दुनिया भर के बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा के रूप में म महापरिनिर्वाण हुआ था। फोटो–एपी, आफताब आलम सिद्दिकी

(9)

(8)

(3)

(4)

आंख से तिब्बत

से दूसरे) केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (दाएं से दूसरे) को
ायक श्रीमती चंद्रेश कुमारी (बाएं से पहली) और श्री जी. एस. बाली (दाएं से पहले) भी

क में स्थित तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि राज्य के मुख्यमंत्री बी एस यदुरप्पा (बाएं से पांचवें)
टो–टीपीआईई

किंग्स इलवेन पंजाब के बीच आईपीएल मैच का आनंद लेते परम पावन दलाई लामा।
लीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा (बीच में) भी दिख रहे हैं।

में मदद करते रानयाग मठ के भिक्षु।

ूहिक प्रार्थना सभा में सीटीए के गणमान्य लोगों के साथ एक मिनट का मौन रखते हुए

में तैनात सशस्त्र पुलिस बल के जवान।

रोपण की तैयारी में परम पावन दलाई लामा (दाएं), उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश
रूप में मनाते हैं। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनका

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

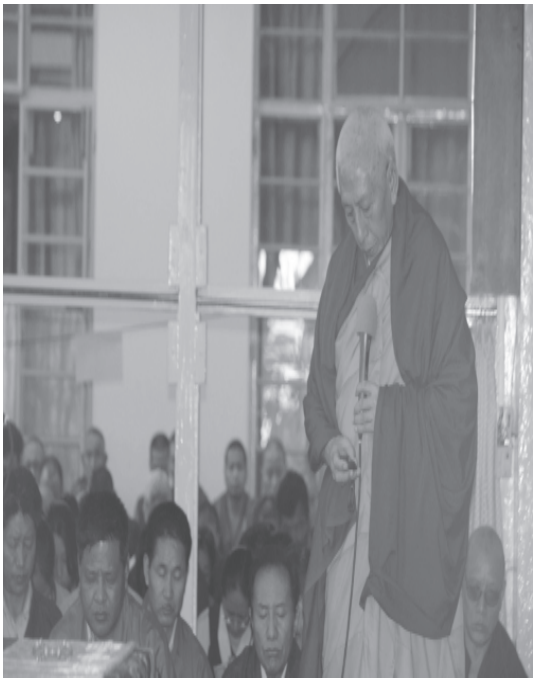

(7)

(6)

सच तो यह है कि चीन अब भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को समर्थन देने के मूड में नहीं लगता।

याद किया कि दिग्गज चीनी नेता डेंग जियोपिंग ने साल 1979 में ही यह आश्वासन दिया था कि "तिब्बत को आज़ादी के अलावा अन्य किसी भी मसले पर बातचीत की जा सकती है और उसका समाधान हो सकता है।"

दलाई लामा ने कहा कि एक बार यदि चीन गंभीरता से बातचीत शुरू करता है तो तिब्बत में रहने वाले तिब्बती नागरिकों को इसमें सक्रियता से भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि तिब्बत में रहने वाले बहुसंख्यक तिब्बती ही मेरे अधिकारी हैं। फिलहाल तो हालत यह है कि अलगाववादी ठहरा दिए जाने के डर से तिब्बत में रहने वाले तिब्बती निर्भय होकर अपनी बात नहीं कह पाते।"

चीनी इंजीनियरों ने तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा

38 गीगावाट का एक जलविद्युत संयंत्र बनाने की योजना पर विचार चल रहा है। यह परियोजना मौजूदा बड़ी परियोजनाओं से डेढ़ गुना बड़ी होगी और इसकी क्षमता ब्रिटेन के राष्ट्रीय ग्रिड के आधे से ज्यादा ही होगी।

(गार्डियन डॉट सीओ डॉट यूके, 25 मई)

चीन के कई जलविद्युत इंजीनियर इस बात के लिए अभियान चला रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी सिरे पर दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना का निर्माण किया जाए। चीन की सोसाइटी फॉर हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग के सह महासचिव झांग बोटिंग ने गार्डियन को बताया कि यारलुंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र के तिब्बती नाम) की धारा पर एक विशाल बांध बनाए जाने से दुनिया को फायदा होगा। जबकि निचली धाराओं पर रहने वाले भारत, बांग्लादेष जैसे देशों ने इस तरह के प्रयास पर गहरी चिंता जाहिर की है। झांग का कहना है कि इस परियोजना के बारे में अध्ययन हुआ है पर अभी कोई योजना तैयार नहीं हुई है। हालांकि एक सरकारी एजेंसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी से पता चलता है कि 38 गीगावाट का एक जलविद्युत संयंत्र बनाने की योजना पर विचार चल रहा है। यह परियोजना मौजूदा बड़ी परियोजनाओं से डेढ़ गुना बड़ी होगी और इसकी क्षमता ब्रिटेन के राष्ट्रीय ग्रिड के आधे से ज्यादा ही होगी। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पर्यावरण नीतियों के तिब्बती विद्वान ताशी सेरिंग के अनुसार ब्रह्पुत्र नदी पर चीन सरकार पहले से ही करीब 28 बांध बना चुकी है या कुछ पर काम चल रहा है।

सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करेगा चीन

(बीजिंग, आईबीएन लाइव, 28 मई, 2010)

भारतीय अधिकारियों ने गुरुवार को तो इस बारे में बड़ी सकारात्मक तस्वीरें दिखाईं कि वे संयुक्त राश्ट्र में सुधार या सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए चीन का समर्थन हासिल कर लेंगे या इस बारे में कुछ समझ तो बन ही चुकी है। पर सच तो यह है कि चीन अब भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को समर्थन देने के मूड में नहीं लगता। भारत की विदेश सचिव निरुपमा राव ने कहा कि जब भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने अपने बीजिंग दौरे के समय चीनी नेतृत्व के सामने यह मसला उठाया तो उनकी तरफ से काफी "प्रगतिशील एवं समझदारी" भरा रवैया अपनाया गया। निरुपमा राव ने कहा था कि इस मसले पर चीन ने जिस तरह का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया उससे साबित होता है कि भारत की दावेदारी कितनी वैधानिक है। लेकिन सच तो यह है कि गुरुवार की वार्ता के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस बारे में चीन का रुख क्या है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील और चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ के बीच वार्ता के बाद जारी बयान में कहीं से यह नहीं लगता है कि चीन संयुक्त राष्ट्र में सुधार या सुरक्षा परिशद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया गया है।

गुरुवार को चीनी अधिकारियों ने कहा कि उनका समर्थन पहले के बिंदुओं पर ही है यानी उनके रुख में बदलाव नहीं आया है। यह पूछने पर कि क्या इसका मतलब यह है कि वेन के भारत दौरे के बाद से ही चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, विदेश सचिव राव ने कहा कि चीन का रुख हमेशा स्थिर नहीं रहता है। राव ने कहा, "यदि आप हमारे प्रधानमंत्री के बीजिंग दौरे के बाद साल 2008 का उनका बयान देखें तो यह उनके पहले के बयान (2005) से काफी अलग है

और वे अब इस रुख पर आगे बढ़ रहे हैं।" साल 2008 में जारी चीन सरकार के बयान में कहा गया था, "दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों का समर्थन करते हैं और सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने का भी समर्थन करते हैं।"

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान चीनी नेतृत्व के समक्ष इस मामले को उठाया था कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनना चाहता है। राव ने कहा, "राष्ट्रपति का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया गया और जैसे सकारात्मक सेंटीमेंट रहे उससे यह पता चलता है कि वे इस मसले पर भारत से जुड़ रहे हैं और हम जो कहना चाहते हैं, उसे समझ रहे हैं।

विदेश सचिव ने चीन के बयान को एक आगे बढ़ने वाला कदम और सकारात्मक घटना बताया। उन्होंने कहा, "अब हम चीन के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे और इस बारे में उनसे बात करेंगे।" उन्होंने कहा कि इस बारे में चीन की प्रतिक्रिया कहीं से भी अपने को बचाने वाली या राजनयिक भाषा वाली नहीं लगती।

चीन ने प्रतिभा पाटील के सामने उठाया तिब्बत मसला

(इंडियन एक्सप्रेस, 28 मई, 2010)

दलाई लामा की भारत में "गतिविधियों" को लेकर चीन की की चिढ़ से यहां राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील की बातचीत में थोड़ी खलल पैदा हो गई, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी विवादित मसले से बचने का पूरा प्रयास किया था। चीन की पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (सीपीपीसीसी) के चेयरमैन जिया क्विंगलिन ने पाटील के साथ अपनी बातचीत में तिब्बत और दलाई लामा की "गतिविधियों" का मसला उठाया। जिया चीनी नेतृत्व में पदानुक्रम के लिहाज से चौथे स्थान पर आते हैं। इसके एक दिन पहले ही पाटील ने चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से वार्ता की थी, लेकिन तब ऐसा कोई मसला नहीं उठाया गया था। 2196 सदस्यों की ताकतवर सीपीपीसीसी के प्रमुख जिया ने दलाई लामा को एक आध्यात्मिक हस्ती से ज्यादा राजनीतिक नेता बताया। सीपीपीसीसी चीन की शीर्ष राजनीतिक सलाहकार निकाय है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि जिया से बातचीत के दौरान पाटील ने दलाई लामा को भारत में रहने वाला एक आध्यात्मिक नेता बताया। बताया जाता है कि तिब्बत के मसले पर पाटील ने जिया से कहा कि भारत तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र को चीन का हिस्सा मानता है और भारत में चीन विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ने दो साल पहले भारत से गुजरने वाले ओलंपिक मषाल रैली का उदाहरण दिया, जब सरकार ने इस बात के पूरे इंतजाम किए थे कि इसमें किसी तरह का खलल न पड़ने दिया जाए। हालांकि, इस बारे में जब भारतीय अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए कहा कि चीनी पक्ष द्वारा यह मसले उठाए जाने में नया कुछ नहीं है और हम इस बारे में बात करते रहेंगे।

चीन के क्येगुडो भूकंप में मरने वालों की संख्या 2698 तक पहुंची

(फायूल, धर्मशाला, 31 मई)

चीनी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि करीब छह हफ्ते पहले उत्तर–पूर्व तिब्बत के क्येगुदो में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का अंतिम आंकड़ा 2,698 तक पहुंच गया है। इसके पहले अप्रैल माह में चीन सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 2,200 और घायलों की संख्या 12,000 बताई गई थी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के अनुसार क्विंघई के वाइस गवर्नर झांग ग्वांगरांग ने पत्रकारों को बताया कि 14 अप्रैल को आए भूकंप के बाद मरने वालों के इस आंकड़े के अलावा करीब 270 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। इस विनाशकारी भूकंप में युशु काउंटी के हजारों मकान नष्ट हो गए हैं। झांग ने संवाददाता सम्मेलन में बताया अभी तक 2,687 लाषों की पहचान हो चुकी है, लेकिन 11 शव की पहचान नहीं हो पाई है। कम्युनिस्ट सरकार के अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में 199 विद्यार्थी और एक हांगकांग का

जिया चीनी नेतृत्व में पदानुक्रम के लिहाज से चौथे स्थान पर आते हैं। इसके एक दिन पहले ही पाटील ने चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से वार्ता की थी, लेकिन तब ऐसा कोई मसला नहीं उठाया गया था। 2196 सदस्यों की ताकतवर सीपीपीसीसी के प्रमुख जिया ने दलाई लामा को एक आध्यात्मिक हस्ती से ज्यादा राजनीतिक नेता बताया।

यदि इस सुझाव पर अमल किया जाता है तो इससे इंटरनेट पर जनता की अभिव्यक्ति पर कड़ा सरकारी नियंत्रण हो जाएगा।

निवासी नागरिक भी है। हालांकि, अपुष्ट सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। शिनहुआ के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिचर पैमाने पर 7.1 थी, हालांकि अमेरिकी भूगर्भ सर्वे के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.9 ही थी।

शनिवार को इस क्षेत्र में 5.4 तीव्रता का एक और भूकंप आया। हालांकि, चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार यह भूकंप 5.7 तीव्रता का था। इसमें किसी के घायल होने या नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है। पिछले माह चीन ने कहा था कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को फिर से आबाद करने में तीन साल लग जाएंगे क्योंकि यह काफी दुर्गम क्षेत्र है।

दो साल के बाद चीन के भूकंप में गायब लोगों को मृत माना गया

(एएफपी, बुधवार, 12 मई, बीजिंग)

यहां के सर गुल लो पहाड़ पर हो रहे खनन कार्य का पिछले साल भी भारी विरोध हुआ था। खबरों के अनुसार इस बार विरोध प्रदर्शनकारियों ने सांगषेन, छोतेन और देशो स्थित तीन खानों पर काम रुकवाने के लिए जबर्दस्त प्रदर्शन किया।

चीन के सिचुआन प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप के दो साल बाद हजारों गायब हो चुके लोगों के परिवारों को आखिरकार बुधवार को यह रजिस्टर कराने का अधिकार मिला कि उनके परिवार का प्रिय सदस्य मृत हो चुका है। चीनी कानून के तहत भूकंप में गायब 18,000 लोगों के परिवारों ने दो साल बाद अपने प्रियजन के मृत होने का पंजीकरण करवाया।

मई, 2008 में आए भूकंप में करीब 70,000 लोग मारे गए थे। इस भूकंप से दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के कई हिस्सों में भारी विनाश हुआ था और इससे बीजिंग ओलंपिक की तैयारी में लगे देश चीन को भारी झटका लगा था।

सरकारी नियंत्रण वाले प्रेस ने भूकंप पर त्वरित सरकारी प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए बुधवार को सरकार की खुलकर तारीफ की, लेकिन आलोचकों ने भूकंप में मारे गए उन हजारों बच्चों के सम्मान में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जो खराब सरकारी इमारतों के ढह जाने की वजह से मारे गए थे। प्रमुख कलाकार–कार्यकर्ता अई वीवेई ने एएफपी को बताया, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वे 12 मई के भूकंप की पष्ठभूमि को बेहतर तरीके से समझें और यह भी समझें कि किस तरह से इसमें सामाजिक एवं प्रषासनिक उपेक्षा का हाथ है और कैसे पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है।

चीन में इंटरनेट पर अज्ञात नाम से टिप्पणी पर रोक लगेगी

(बीबीसी, बुधवार, 12 मई, बीजिंग)

चीन सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अपने नागरिकों को इंटरनेट पर टिप्पणी के लिए छद्म नामों के इस्तेमाल से रोका जाए। चीन सरकार के सूचना विभाग के प्रमुख वांग चेन ने वरिष्ठ चीनी नेताओं के साथ एक बैठक में यह सुझाव दिया है। यदि इस सुझाव पर अमल किया जाता है तो इससे इंटरनेट पर जनता की अभिव्यक्ति पर कड़ा सरकारी नियंत्रण हो जाएगा। चीन में पहले से ही नागरिकों के इंटरनेट इस्तेमाल पर मजबूत पहरा है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के संदेह वाले लोगों को पकड़ने में मदद करने के लिए इंटरनेट कंपनियों को मजबूर करने हेतु चीन सरकार ने राज्य गोपनीयता कानून में बदलाव किया है।

मारखम में खनन का विरोध कर रहे पांच ग्रामीण घायल

(फायूल, धर्मशाला, 15 मई)

तिब्बत स्वायत्तषासी क्षेत्र –टीएआर– के मारखम काउंटी में पहाड़ों पर चल रहे खनन कार्यों का हजारों तिब्बती ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया है। इस विरोध प्रदर्शन में पांच ग्रामीण घायल हो गए हैं, जिसमें से दो महिलाएं हैं। तिब्बती लोग इन पहाड़ों को पवित्र मानते हैं। सूत्रों के अनुसार खनन कार्यों को सुरक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद थे, इसके बावजूद जनता विरोध पर अड़ी रही। मारखम काउंटी परंपरागत रूप से पूर्वी तिब्बत के खम प्रांत का हिस्सा रहा है। यहां के सर गुल लो पहाड़ पर हो रहे खनन कार्य का पिछले साल भी भारी विरोध हुआ था। खबरों के अनुसार इस बार विरोध प्रदर्शनकारियों ने सांगशेन, छोतेन और देशो स्थित तीन खानों पर काम रुकवाने के लिए

जबर्दस्त प्रदर्शन किया। नाम न छापने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया, पवित्र पहाड़ों को दोहन से रोकने के लिए तिब्बतियों ने अपना खेती–धंधा भी छोड़ दिया है। इन विरोध प्रदर्शनों में पांच विरोध प्रदर्शनकारी–दो महिलाएं और तीन मर्द– घायल हुए हैं और एक प्रदर्शनकारी ने एक टूटी हुई बोतल से आत्महत्या का भी प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उनकी जमकर पिटाई की।

लाबरांग में चीनी पुलिस की खुलेआम फायरिंग से 15 तिब्बती मारे गए

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 18 मई)

आमदो लाबरांग में शनिवार को एक सीमेंट फैक्टरी के सामने षांतिपूर्ण प्रदर्षन कर रहे तिब्बतियों पर चीनी पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी सीमेंट कारखाने द्वारा स्थानीय पर्यावरण में फैला रहे प्रदूषण और स्थानीय तिब्बतियों की धार्मिक भावना से खिलवाड़ की खिलाफत कर रहे थे। वाशिंगटन के इंटरनेशनल कैंपेन फॉर टिबेट के अनुसार इस गोलीबारी के बाद 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग पुलिस की गोलीबारी और पिटाई से घायल हुए हैं। हालांकि, अभी तक किसी की मौत होने की खबर नहीं है। परंपरागत तिब्बती प्रांत आमदो के जियाहे काउंटी (लाबरांग) के मादांग टाउनशिप में रहने वाले 7 ग्रामीण तिब्बतियों ने एक रिट याचिका दायर कर आमदो सीमेंट कारखाने द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर नाराजगी जाहिर की है। इस कारखाने में 600 कर्मचारी काम करते हैं। प्रदूषण की चिंता के अलावा, स्थानीय तिब्बतियों का कहना है कि यह कारखाना एक धार्मिक महत्व के स्थान पर बनाया गया है।

चीन के निशाने पर हैं तिब्बती कलाकार और बुद्धिजीवी

(रायटर्स, बीजिंग, 18 मई, 2010)

साल 2008 में समूचे तिब्बत में फैली हुई अशांति के बाद अपने क्षेत्र के भविष्य को लेकर खुलकर चर्चा की मांग करने वाले तिब्बती बुद्धिजीवियों एवं कलाकारों के खिलाफ चीन सख्त कार्रवाई कर रहा है। एक विदेशी संगठन ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। इंटरनेशल कैंपेन फॉर टिबेट की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 30 से ज्यादा लेखकों, ब्लॉगर, गायक और पर्यावरणविद को हिरासत में लिया गया है या जेल भेज दिया गया है। इनमें से ज्यादातर ने तिब्बती क्षेत्र के लोगों के बारे में विचारों या सूचनाओं का आदान–प्रदान किया था।

अ रेजिंग स्टोर्म: द क्रैकडाउन ऑन टिबेटन राइटर्स एंड आर्टिस्ट आफ्टर टिबेट्स स्प्रिंग 2008 प्रोटेस्ट नामक इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कितने बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया है।

इंटरनेशल कैंपेन फॉर टिबेट की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 30 से ज्यादा लेखकों, ब्लॉगर, गायक और पर्यावरणविद को हिरासत में लिया गया है या जेल भेज दिया गया है।

सर्था में विरोध प्रदर्शन कर रहे 2 तिब्बती गिरफ्तार

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 19 मई)

चीनी पुलिस ने सर्था काउंटी के दो तिब्बती नागरिकों को रविवार, 16 मई की रात को गिरफ्तार कर लिया है। सर्था के मूल निवासी और अब धर्मशाला में रहने वाले एक तिब्बती नागरिक ने यह जानकारी दी है। सर्था खेकोर गांव के कालडेन एवं सोनम तोबदेन ने तिब्बत में मानवाधिकारों की बहाली और निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामा की वापसी की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया था जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इन दोनों नागरिकों ने अपनी मांग को लेकर कई पत्रक भी बांटे। जब वे दीवारों पर पत्रक चिपका रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों नागरिकों को फिलहाल सर्था काउंटी के कारावास में रखा गया है। उनके परिवार एवं रिश्तेदारों का उनसे मिलने का प्रयास निष्फल साबित हुआ है क्योंकि पुलिस इसकी इजाजत नहीं दे रही है।

सर्था खेकोर गांव के कालडेन एवं सोनम तोबदेन ने तिब्बत में मानवाधिकारों की बहाली और निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामा की वापसी की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया था जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

अब चीन ने ल्हासा में फोटोकॉपी सेवा पर भी सख्त निगरानी शुरू की

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 19 मई)

चीनी कम्युनिस्ट शासकों ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में एक नया नियम लागू कर दिया है जिसके अनुसार प्रिंटिंग और फोटोकॉपी सेवा पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने कई अधिकारियों के हवाले से कहा है कि यह "गैरकानूनी गतिविधियों" को रोकने के लिए यह सख्ती बरती जा रही है। ल्हासा इवनिंग न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार गत 10 मई को शहर के रेप्रोग्राफी सेक्टर के प्रबंधन की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए नियमों के अनुसार ल्हासा में प्रिंटिंग या फोटोग्राफी कारोबार करने वाले ऑपरेटर को पुलिस और संबंधित अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी और शहर के मूल निवासी या अस्थायी तौर पर निवास प्रमाणपत्र हासिल कर चुके लोग ही यह कारोबार कर पाएंगे। फोटो कॉपी सेवा देने वाले कारोबारी को सख्ती से सभी ग्राहकों का नाम–पता दर्ज करना होगा और जिस व्यक्ति के पास आईडी कार्ड होगा उसी को सेवा दी जा सकेगी। दुकानदार ग्राहक का नाम, पता और आईडी नंबर एक रजिस्टर में दर्ज करेगा। पुलिस को रेप्रोग्राफी सेवाएं देने वाले कंपनी या दुकानदार की कड़ाई से जांच करनी होगी और स्थानीय पुलिस को लगातार इस बात की निगरानी करनी होगी कि नए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। चाइना डेली के अनुसार जो लोग किसी भी तरह से गैरकानूनी गतिविधि में खुद लिप्त होने या उसमें मदद करते पाए गए उन्हें अपनी दुकान बंद करनी होगी और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नए नियमों के अनुसार ल्हासा में प्रिंटिंग या फोटोग्राफी कारोबार करने वाले ऑपरेटर को पुलिस और संबंधित अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी और शहर के मूल निवासी या अस्थायी तौर पर निवास प्रमाणपत्र हासिल कर चुके लोग ही यह कारोबार कर पाएंगे। फोटो कॉपी सेवा देने वाले कारोबारी को सख्ती से सभी ग्राहकों का नाम–पता दर्ज करना होगा और जिस व्यक्ति के पास आईडी कार्ड होगा उसी को सेवा दी जा सकेगी।

चीन ने जोमदा काउंटी के 6 भिक्षुओं को गिरफ्तार किया

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 20 मई)

चीनी प्रशासन ने शनिवार 15 मई को जोमदा काउंटी के थांगपू टाउनषिप में स्थित वारा मठ के चार भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया है। यह काउंटी तिब्बत स्वायत्तषासी क्षेत्र के चामदो प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित है। इन भिक्षुओं पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने साल 2008 के मार्च माह में काउंटी मुख्यालय में हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) के अनुसार इसी मठ के दो अन्य वरिष्ठ भिक्षुओं को इस आरोप में हिरासत में ले लिया गया है कि वे "देशभक्ति शिक्षा अभियान के तहत अपने भिक्षुओं को शिक्षित करने में विफल रहे हैं।" इन भिक्षुओं को शनिवार एवं रविवार के भोर में ही उनके मठों से उठा लिया गया। 25 साल के थिनले और 27 साल के नांगसे को उनके कमरों से गिरफ्तार किया गया, जबकि सोएगॉन को तब गिरफ्तार किया गया जब वह अन्य लोगों को मठ में जन सुरक्षा ब्यूरो (पीएसबी) के अधिकारियों के आने की चेतावनी दे रहे थे। 29 साल के भिक्षु केलसांग ग्यूर्मी को उनके घर से हिरासत में लिया गया। पीएसबी के अधिकारियों ने पहले मठ में केलसांग की तलाष की और जब वे नहीं मिले तो वे उनके घर पहुंच गए। चारों भिक्षुओं को फिलहाल जोमदा काउंटी के पीएसबी हिरासत केंद्र में रखा गया है।

परम पावन दलाई लामा के 75वें जन्म दिन समारोह के अवसर पर कशग द्वारा जारी बयान

मंगलवार, 6 जुलाई, 2010

तिब्बती जनता के आध्यात्मिक एवं सांसारिक प्रमुख परम पावन दलाई लामा के 75वें जन्म दिन समारोह के शुभ अवसर पर कशग, तिब्बत के भीतर एवं तिब्बत के बाहर रहने वाले सभी तिब्बतियों की तरफ से और दुनिया भर में मौजूद उनके सभी शिष्यों एवं शुभेच्छुओं की तरफ से उनके प्रति सम्मान प्रकट करता है और प्रार्थना करता है कि वह सैकड़ों साल तक जिएं। अपने बचपन से लेकर अब तक परम पावन दलाई लामा ने सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति एवं करुणा की भारी चेतना विकसित की है, विभिन्न तरह के मानसिक स्थिति के लोगों की जरूरतों की पूर्ति कर मानवता की भारी सेवा की है और साथ ही, बुद्ध शाक्यमुनि के समूचे शिक्षाओं को बचाए रखने और उसके

प्रचार में योगदान दिया है जिसे कि बौद्ध जगत में चौथे मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। खासकर अत्याधुनिक युग में परम पावन दलाई लामा ने दुनिया के सभी धर्मों के आस्तिकों और नास्तिकों को समान रूप से प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्रदान किया है।

धर्म की सीमाओं से ऊपर होते हुए परम पावन ने अपने "धर्मनिरपेक्ष नीतिशास्त्र" के तहत अभूतपूर्व और समय अनुकूल परामर्श दिए जिसमें उन्होंने बुनियादी मानवीय मूल्यों एवं अंतर धार्मिक सामंजस्य और हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके साझा भलाई के लिए सहअस्तित्व के प्रचार–प्रसार के द्वारा सार्वभौमिक जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा तिब्बत मसले को हल करने के लिए परम पावन दलाई लामा परस्पर फायदेमंद मध्यम मार्ग नीति लेकर आए और इसे हासिल करने के लिए अहिंसक साधनों का सहारा लेने की बात कही। परम पावन ने निर्वासित तिब्बती राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को एक सच्चे लोकतंत्र में बदल दिया। किसी भी तरीके से हम परम पावन दलाई लामा के प्रति कृतज्ञता के कर्ज को चुका नहीं सकते। लेकिन उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उन सबको गहराई से स्वीकार करते हुए हम अपने आप को पुनः यह वचन देते हैं कि उन्होंने हमको जो कई बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उनको असल व्यवहार में लागू करेंगे। परम पावन दलाई लामा के साथ अभी तक कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ है जिसकी मुख्य वजह यह है कि उनके अंदर परोपकार की भावना है और उनके कर्म अच्छे हैं, उनको तिब्बत के अभिभावक देवताओं का संरक्षण मिला हुआ है, तिब्बती जनता की सामूहिक अच्छाइयों का फल उनके साथ है और खासकर भारत की महान जनता और भारत की केंद्र और राज्य सरकारों ने उनकी लगातार सहायता एवं सहयोग की है। हम इन सभी लोगों को अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं, खासकर उन लोगों को जिन्होंने परम पावन की सुरक्षा का जिम्मा संभाला हुआ है। हम इन सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे इस संबंध में अपने सहयोग एवं सहायता को और बढ़ा दें।

महान करुणा के साथ परम पावन के दिन की शुरुआत और अंत समूचे मानवता की भलाई के लिए ही होती है। "पृथ्वी और प्रकृति के अन्य महान तत्वों एवं आकाश की तरह मैं भी हमेशा ऐसे व्यक्ति के रूप में सेवा कर सकूं जो अनंत प्राणियों के असंख्य समस्याओं का समाधान कर सकता हो", महान बोधिसत्व शांतिवेद के इस पंक्ति से प्रेरित परम पावन ने अपने को प्राणियों की सेवा में झोंक दिया है। हम उनके इन सभी प्रयासों की तारीफ करते हैं, लेकिन यह सब निश्चित रूप से परम पावन के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। आमतौर पर समूचे मानवता के लिए और खासकर तिब्बती जनता के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक फायदों के लिए परम पावन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम उनसे विनती करना चाहते हैं कि कृपया अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इस बात पर ध्यान दें कि उनका दैनिक कार्यक्रम उनके अच्छे स्वास्थ्य के रास्ते का अड़चन न बनें।

चीन जनवादी गणराज्य के कई नेता, जो सही या गलत का चुनाव करने के मामले में अंधे हो चुके हैं और जिनमें अपने पूर्वाग्रह या अल्पकालिक व्यक्तिगत या राजनीतिक सत्ता का लाभ उठाने की सोच की वजह से दूरदर्शिता का अभाव है, परम पावन के खिलाफ निरर्थक आरोप लगाने और उनकी झूठी निंदा करने के लिए जन और धन संसाधनों की खुलकर बर्बादी कर रहे हैं। दुनिया भर में परम पावन के ख्यातिपूर्ण कर्मों की बराबरी करने में अक्षम रहने की वजह से उत्पन्न ईर्ष्या की वजह से यह सब हो रहा है। उनके यह कार्य हवा में थूकने जैसे ही हैं जो लौटकर उनके ऊपर ही गिरता है। इस वजह से ही दुनिया भर के लोग यह समझ रहे हैं कि चीन के तानाशाह नेता ऐसे लोग हैं जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं और जो केवल झूठ एवं हिंसा पर भरोसा करते हैं, न कि तथ्यों के आधार पर सत्य को जानने में। इन सबकी वजह से तिब्बतियों को एक रहने में और मदद ही मिली है। हालांकि, जैसा कि वैश्विक मामलों में कई भारतीय एवं तिब्बती समझौतों में कहा गया है कि विपक्ष की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए और उसे

हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके साझा भलाई के लिए सहअस्तित्व के प्रचार–प्रसार के द्वारा सार्वभौमिक जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा तिब्बत मसले को हल करने के लिए परम पावन दलाई लामा परस्पर फायदेमंद मध्यम मार्ग नीति लेकर आए और इसे हासिल करने के लिए अहिंसक साधनों का सहारा लेने की बात कही।

पंद्रहवें निर्वासित तिब्बती संसद के आने वाले चुनाव और कालोन ट्रिपा के तीसरी बार होने जा रहे चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर तिब्बती जनता इस मामले में गंभीर चर्चा एवं बहस में लगी हुई है कि किसे वोट दिया जाए। ऐसे मौके पर लोगों को दूसरे पक्ष के नापाक मंसूबों एवं घुसपैठ से सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा हर तिब्बती नागरिक को अपने लोकतांत्रिक जिम्मेदारी एवं अधिकार से जी न चुराते हुए चुनाव प्रक्रिया में गंभीरता एवं साहस के साथ हिस्सा लेना चाहिए।

नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यह कशग तिब्बत के भीतर एवं बाहर रहने वाले सभी तिब्बती नागरिकों से इस नाजुक समय में कुछ महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता है।

साल 2008 में सामूहिक तिब्बती भावना के साफ प्रदर्शन का परिणाम यह रहा है कि तिब्बती आंदोलन को और खास कर परम पावन की उपलब्धियों एवं महान कार्यों को दुनिया भर के लोगों को समर्थन एवं सहानुभूति हासिल हुआ है। दूसरी तरफ, दूसरा पक्ष तिब्बतियों में और जहां निर्वासित तिब्बती रह रहे हैं वहां के स्थानीय समुदाय के साथ उनका अनबन कराने के लिए अपने सभी राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय ताकत को झोंक दे रहा है। हमारा विरोधी खासतौर से दुनिया भर में परम पावन की गतिविधियों और कार्यों में अड़चन डालने के लिए कई तरह के धोखाधड़ी वाले साधनों का सहारा ले रहा है। कशग तिब्बत के भीतर और बाहर रहने वाले सभी तिब्बतियों से यह जोरदार अपील करना चाहता है कि चीन के इस छल–कपट से सावधान रहें और अपने बीच एकता बनाए रखने और स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए हमेशा सावधान रहें।

पंद्रहवें निर्वासित तिब्बती संसद के आने वाले चुनाव और कालोन ट्रिपा के तीसरी बार होने जा रहे चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर तिब्बती जनता इस मामले में गंभीर चर्चा एवं बहस में लगी हुई है कि किसे वोट दिया जाए। ऐसे मौके पर लोगों को दूसरे पक्ष के नापाक मंसूबों एवं घुसपैठ से सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा हर तिब्बती नागरिक को अपने लोकतांत्रिक जिम्मेदारी एवं अधिकार से जी न चुराते हुए चुनाव प्रक्रिया में गंभीरता एवं साहस के साथ हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव के लिए सही उम्मीदवार का चयन करने में दूसरों की बातों पर चलने की जगह अपने विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कशग सभी तिब्बती नागरिकों से यह निवेदन करना चाहता है कि वे इन बातों पर गंभीरता से विचार करें। पचास साल से भी ज्यादा समय से तिब्बत के भीतर एवं बाहर रहने वाले तिब्बती असहनीय एवं आपातकालीन परिस्थितियों में भी बड़े साहस एवं मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और चार से भी ज्यादा पीढ़ियों से तिब्बती अपने धर्म, संस्कृति एवं परंपरा को बचाए रखने में सक्षम हुए हैं। यह सब वास्तव में परम पावन दलाई लामा की कृपा से ही हो पाया है। इसके अलावा, यह तथ्य भी हम सबके लिए गर्व की बात है कि लगातार अहिंसक आंदोलन को जारी रखने में तिब्बतियों की भावना कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ी है। दुनिया और अपने देश में हो रहे बदलावों को देखने पर हमें ऐसा लगता है कि तिब्बत का मसला अब एक हल की ओर बढ़ रहा है। फिर भी, परम पावन अक्सर यह कहते रहे हैं कि हमें सबसे अच्छे की आशा करनी चाहिए और सबसे खराब के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए यदि तिब्बत की समस्या के हल में देर होती है, तो तिब्बत के भीतर और बाहर रहने वाले तिब्बतियों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपना उत्साह खोए बिना अच्छे नैतिक आचरण के अपने विशेष चरित्र को बनाए रखें। अच्छा नैतिक आचरण न केवल तिब्बतियों का प्रतीक है, बल्कि चीनी और दुनिया भर के अन्य लोगों के लिए हमारे आंदोलन के प्रति लगाव एवं समर्थन का स्रोत भी है। इसी प्रकार, युवा तिब्बतियों को सामान्य अध्ययन के प्रति ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए और खासकर परंपरागत एवं आधुनिक, दोनों तरह की शिक्षा में पारंगत पेशेवर बनने का प्रयास करना चाहिए। परम पावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में जबर्दस्त बहुमत में तिब्बतियों द्वारा स्वीकार की गई परस्पर फायदेमंद मध्यम मार्ग नीति तिब्बत मसले को हल करने का एकमात्र रास्ता है। कशग इस तथ्य के आधार पर इन दिनों इस नीति को आगे बढ़ा रही है कि इसको तिब्बती जनता के जबर्दस्त बहुमत का समर्थन हासिल है और निर्वासित तिब्बती संसद ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। हमारा मानना है कि सभी तिब्बती अपने विवेक के आधार पर इस नीति के गुणों को समझते हुए तहे दिल से इसका समर्थन करेंगे।

अंत में कशग यह प्रार्थना करता है कि परम पावन दीर्घायु हों और उनकी सभी मनोकामनाएं आसानी से पूरी हों। हमारी कामना है कि तिब्बत मसले के सच की जल्दी ही विजय हो।

– कशग